ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, मंगलवार 23 जुलाई 2024

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 1 अंक 143

सस्ता और महंगा- मोबाइल फोन सस्ते होंगे:सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई; एक साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम

अब 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स

क्रम	पुराने स्लैब	पुरानी दर	नए स्लैब	नई दर
1	3 लाख	0%	3 लाख	0%
2	3-6 लाख	5%	3-7 लाख	5%
3	6-9 लाख	10%	7-10 लाख	10%
4	9-12 लाख	15%	10-12 लाख	15%
5	12-15 लाख	20%	12-15 लाख	20%
6	15 लाख से ज्यादा	30%	15 लाख से ज्यादा	30%

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली.बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।

हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या महंगे ये तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। एक साल में सिलेंडर 300 रुपए सस्ता, सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे बीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

मोबाइल फोन, सोना-चांदी सस्ते होंगे

प्रोडक्ट	वजह
फोन और चार्जर	मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% की
सोना-चांदी	सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की
प्लेटिनम	प्लेटिनम पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15.4% घटाकर 6.4% कर दिया गया
कैंसर की 3 दवाएं	कैंसर की दवाओं से ड्यूटी हटाई
इलेक्ट्रॉनिक सामान	आक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई
सोलर पैनल	सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट
रेयर मिनरल्स	25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई
फिश फीड	फिश फीड की कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की

न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री:NDA के सहयोगी नीतीश को 59 हजार करोड़, नायडू को 15 हजार करोड़

24 न्यूज अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।

बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।

मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की। न्यू टैक्स रिजीम में राहतः टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआः कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं।

एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़, MSP पर कोई ऐलान नहींः सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई।

हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगीः शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मलिेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

महिलाओं और लड़कियों के लिएः महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।

सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिएः सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।

सरकार की एकल पट्टा जांच कमेटी रद्द करने की मांग:रिटायर्ड IAS संधू ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, पूर्व मंत्री धारीवाल भी हैं जांच के दायरे में

28 जून को बनाई थी कमेटी

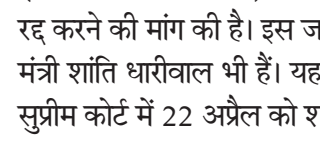

24 न्यूज अपडेट

जयपुर. 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय में एकल पट्टा प्रकरण को लेकर आरोपी रहे जीएस संधू ने भजनलाल सरकार की जांच कमेटी को रद्द करने की मांग की है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा- मामले में राज्य सरकार अपना जवाब दे चुकी है, उसमें उन पर कोई भी अपराध बनना नहीं पाया है। मामले में पहले भी एफआर लग चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट से भी अभियोजन पक्ष भी मामला वापस ले चुका है। ऐसे में इस स्तर पर राज्य सरकार की ओर से मामले के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि भजनलाल सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरएस राठौड़ की अध्यक्षता में 28 जून को कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में गृह विभाग के एसीएस व यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव को भी शामिल किया गया था। संधू ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) में प्रार्थना पत्र दायर करके कमेटी को रद्द करने की मांग की है। इस जांच के दायरे में तत्कालीन UDH मंत्री शांति धारीवाल भी हैं। यह है मामला भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को शपथ पत्र पेश करते हुए करीब 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में एकल पट्टा मामले में विधायक शांति धारीवाल सहित तीन अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता है। एकल पट्टा प्रकरण में पूरी तरह से नियमों की पालना की गई थी। वहीं, इसमें राज्य सरकार को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान भी नहीं हुआ है।

NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगी:सुप्रीम कोर्ट ने माना- पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं; कल से काउंसलिंग शुरू होगी

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. NEET केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

CJI ने कहा- फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।

कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की है।

NEET केस में CJI की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। CJI ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब 24 जुलाई से काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

जस्टिस जे बी पारदीवाला | चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ | जस्टिस मनोज मिश्रा

CJI : विवादित सवाल को लेकर जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है। NTA ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। CJI : कोर्ट ने केस में NTA, केंद्र सरकार, और CBI से हलफनामा मांगा था। हमने केस की सुनवाई 4 दिनों तक की। CBI के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा का पक्ष भी सुना। हमनें सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इस तरीके के केस में जहां फैसले का असर 23 लाख बच्चों पर पड़े, वहां फैसला जल्द से जल्द सुनाना होगा।

CJIः इस केस में कोर्ट से इन पॉइंट्स के आधार पर रीएग्जाम का आदेश देने का निवेदन किया जा रहा है -

1. क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एग्जाम में सिस्टम के लेवल पर गड़बड़ी हुई
2. एग्जाम 4750 सेंटर्स पर 571 शहरों और विदेश में 14 शहरों में हुआ था।
3. 24 लाख स्टूडेंट्स ने 1 लाख 80 हजार सीटों के लिए परीक्षा दी।
4. कोर्ट को ये बताया गया कि 50% परसेंटाइल स्कोर करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी सीट पक्की।
5. एग्जाम में 180 सवाल होते हैं और हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग की जाती है।

संपादकीय : विकास का अर्थ

आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखाजोखा पेश किया जाता है। इसी आधार पर अहगामी वर्ष के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं। इस वर्ष चूंकि आम चुनाव थे, पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। आज इस वर्ष के लिए आम बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछला वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा। कोरोना काल के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी की दर निरंतर घट रही है। भारत की कुल श्रमशक्ति में से सत्तावन फीसद स्वरोजगार में लगी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर जरूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतरराष्ट्रीय स्थितियों से तुलना करें तो इस पर अपेक्षाकृत काबू पाया जा सका है। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की वजह से जल्दी ही महंगाई की लक्षित दर हासिल कर ली जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। इस वर्ष विकास दर के साढ़े छह से सात फीसद रहने का अनुमान है। 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत रेखांकित की गई है। हालांकि वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकती हैं। पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। यों पहले से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक बजटीय प्रावधान और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। निजी उद्योगों की सुविधा के लिए कर, कर्ज आदि में छूट के अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया। इससे पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में नौ फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वित्तमंत्री ने कहा है कि अब निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने का वक्त है। अगले वित्तवर्ष में बजट घाटा घट कर साढ़े चार पवैसद तक रह जाने की संभावना जताई गई है। नए बजट में कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हवाई सेवा क्षेत्र को बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बिठाने, ड्रोन निर्माण में तेजी लाने और राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जाहिर है, आम बजट क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं पर बल होगा। में इन हालांकि इस सर्वेक्षण की विपक्ष ने अतिरंजित और आंकड़ों का खेल बताया तथा बजट में व्यावहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। दरअसल, आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यावहारिक घरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नजर नहीं आता। एक तरफ तो आंकड़ों में तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था की गुलाबी तरवीर नजर आती है, मगर आम जनजीवन के स्तर पर बेहतरी के कोई संकेत नजर नहीं आते। बेशक सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने का दम भरती है, पर हकीकत यह है कि लोग रोजमर्रा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और क्रयशक्ति मटने की वजह से परेशान हैं। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को भरोसे का कोई काम मिलना कठिन बना हुआ है। जिस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, वह उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। इसलिए बजट में अगर गंभीरता से व्यावहारिक नीतियों पर विचार नहीं होगा, ती मुश्किलें आसान नहीं होंगी।

खेती और खुदकुशी

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मगर यहां के किसान आज भी कई तरह की समस्याओं और परेशानियों से घिरे हुए हैं। यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की एक रपट के मुताविक, इस वर्ष जनवरी से जून के बीच राज्य में 1,267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे और इनमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा थे। इसी तरह वर्ष 2021 में कृषि कार्यों में लगे 10,881 लोगों और 2020 में 10,677 लोगों ने अपनी जान दे दी। किसानों की खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कर्ज या आर्थिक संकट को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि इन आर्थिक परेशानियों के भी कई स्तर हैं। मसलन, प्राकृतिक आपदा, कर्ज का बोझ, फसलों की बढ़ती लागत, घटती आय और फसलों के उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र सरकार की रपट में कहा गया है कि राज्य में पिछले छह माह में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल में सामने आए हैं। बहुत से किसान खेती के लिए बैंक और साहूकारों से कर्ज लेते हैं और अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल वर्वाद ही जाए वा उत्पादन कम हो, तो उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। उर्वरक, खेती के लिए उपकरण और सिंचाई पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लिहाजा, किसानों की आर्थिक परेशानियां बढ़नी स्वाभाविक हैं। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग भी लंबित है। दूसरी ओर, उद्योग जगत के ऋणों के प्रति सरकार के नजरिए में जो नरमी देखी जाती है, यह किसानों के लिए नहीं दिखती। ऐसे में किसानों की समस्याओं की जटिलता अगर उन्हें आत्महत्या के कगार पर ले जाती है तो इसे एक नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस और कारगर उपाय किए जाने जरूरत है, अन्यथा यह स्थिति और जटिल होगी।

स्कूल टीचर ने छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज:लिखा- पास होगी तो मुझे क्या मिलेगा; ग्रामीणों ने की स्कूल पर तालाबंदी, विभाग ने किया एपीओ

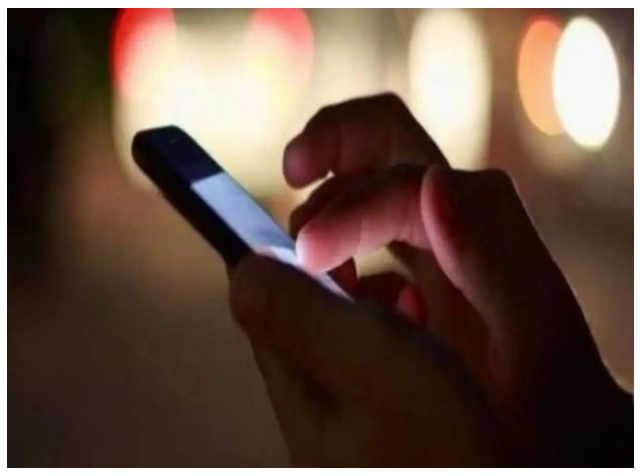

24 न्यूज अपडेट

आसपुर. डूंगरपुर के साबला ब्लॉक के निठाउवा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में टीचर की ओर से नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद भी विभागीय कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को स्कूल की छुट्टी करा दी। इसके बाद स्कूल पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, मामले में कार्रवाई करते हुए आसपुर एसडीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर को एपीओ कर दिया है।

6 महीने पहले हो चुकी है शिकायत

गांव के लोगों ने बताया कि गांव के स्कूल में कार्यरत टीचर जितेंद्र मीणा (34) आए दिन शराब पीकर स्कूल आता है और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है। जिसकी 6 महीने पहले और 4 महीने पहले भी शिकायत की जा चुकी हैं। मगर विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शिक्षक पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप

ग्रामीणों ने बताया- शुक्रवार को शिक्षक जितेंद्र मीणा ने एक छात्रा को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजे। जिसकी शिकायत छात्रा की मां ने शनिवार (20 जुलाई) को स्कूल के प्रिंसिपल से की थी। जिस पर प्रिंसिपल ने मामले की सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई। मगर विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर आक्रोशित परिजन और गांव वाले मंगलवार सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचे और स्कूल की छुट्टी करा दी। इसके बाद स्कूल पर ताला जड़ दिया। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में भी आरोपी शिक्षक ने छात्रा को मैसेज किए थे। जिसकी शिकायत पर शिक्षक ने मैसेज करना बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने फिर शुक्रवार को छात्रा को मैसेज किया।

समझाइश पर गांव वालों ने खोला ताला

इस दौरान स्कूल की तालाबंदी की सूचना पर आसपुर एसडीएम और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों के साथ समझाइश की। जिस पर गांव वालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई के बाद तालाबंदी खोलने की बात कही। इसके बाद 15 मिनट तक चली समझाइश के बाद स्कूल का ताला खोल दिया। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर जितेन्द्र मीणा को एपीओ कर दिया है। वहीं, परिजनों की ओर से निठाउवा थाना पुलिस को रिपोर्ट भी दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले को लेकर निठाउआ थाने के एसएचओ भवानी शंकर ने बताया- रिपोर्ट के आधार पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।

बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान:हवा में आर्द्रता 30% कम हुई तो 3 दिन में सूख जाएगी, 70 हैक्टेयर में की बुवाई

24 न्यूज अपडेट

बांसवाड़ा. बांसवाड़ा जिले में 72 हजार हैक्टेयर में सोयाबीन की फसल की बुवाई हुई है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में जमीन में नमी कम हो गई है। यदि तेज धूप निकले और हवा में आर्द्रता 30 प्रतिशत से कम हो जाए तो फसल 3 दिन में सूख जाएगी। बांसवाड़ा जिले में ज्यादातर लाल-काली मिट्टी है। काली मिट्टी में अन्य के मुकाबले पानी को सोख कर अपने अंदर समाहित करने की ज्यादा क्षमता होती है। बावजूद इसके सोयाबीन की फसल पर सूखने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कारण बारिश नहीं होना है। जिले में सोयाबीन की फसल बोई जा चुकी है। जरूरत थी एक अच्छी बारिश की पर नहीं हुई। अब जो फसलें लहलहाने लगी हैं।

वह आर्द्रता के कारण। हवा की नमी को सोखकर सोयाबीन की फसल जिंदा है। यदि तेज धूप निकलने लगे और आर्द्रता 30 प्रतिशत या इससे कम हो जाए तो 3 दिन में सोयाबीन की फसल सूख सकती है। इसलिए सक्षम किसानों को सलाह दी गई है कि यदि उनके पास संसाधन है तो पानी जरूर लगाएं।

तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील

सोयाबीन की फसल तापमान के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। यही कारण है कि बारिश नहीं होने और तेज गर्मी पड़ते ही फसलें सूख जाती हैं। हालांकि देश के वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ हद तक काबू पाया है। वर्तमान में 2 किस्में ऐसी हैं। जो तापमान को सहन कर सकती हैं। आने वाले दिनों में जो भी सोयाबीन की नई किस्में तैयार होंगी। वह इन्हीं के आधार पर तैयार होंगी।

कैश क्रोप में पानी की कमी बहुत खलेगी

उपनिदेशक, कृषि विस्तार डॉ. दलीप सिंह का कहना है कि जिले में करीब 72 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई है। बारिश की भारी जरूरत है। यदि कैश क्रोप को पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान होगा। किसान सोयाबीन से बड़ी उम्मीद लगाता है क्योंकि फसल तैयार होते ही अच्छी दाम में बिक जाती है।

बारिश के लिए मेढक-मेढकी का विवाह कराया:सात फेरे भी कराए, मटकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग को जलमग्न किया

24 न्यूज अपडेट

बांसवाड़ा. बारिश की कामना के लिए अब हर दिन नए नए जतन होने लगे हैं। एक तरफ टोटके हो रहे हैं तो दूसरी ओर आस्था भी दिखाई देने लगी है। शहर में ऐसा ही आयोजन चंद्रपोल गेट के निकट देखने को मिला। यहां मंदिर में शिव लिंग को जलमग्न कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जोशी ने बताया कि मान्यता है कि जब भी बारिश नहीं हो और मटकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग को जलमग्न कर दो तो अच्छी बारिश की संभावना बढ़ जाती है।

इधर, बारिश नहीं होने पर डेगली माता चौक में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मदहोश ने मेंढक और मेंढकी की शादी का आयोजन किया। मदहोश ने बताया कि शादी कराने से पहले शुभ मुहूर्त निकाला गया। इसके बाद शादी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उसी प्रकार से किया गया जैसे सामान्य शादी थी। शादी में बारात भी आई और बाजे भी बजाए गए। उन्होंने बताया कि बीते 2 दशक से यह वे आयोजन कराते आ रहे हैं। जिस वर्ष भी बारिश नहीं होती है तो वह ये आयोजन करते हैं। ज्यादातर उनको यह आयोजन सफल रहा है।

घर से 500 मीटर दूर लटका मिला युवक का शव:खेतों में मक्का की फसल से खरपतवार हटा रहा था परिवार

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर. चौरासी थाना क्षेत्र के रंगेला फला डामोर गांव में एक युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घर से 500 मीटर दूर जंगल में शव लटका हुआ था। मृतक अपने घर में इकलौती संतान थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चौरासी थाने के एएसआई छतरसिंह ने बताया- रंगेला फला डामोर निवासी धुलेश्वर पुत्र हाजा डामोर ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया- सोमवार शाम को उसका बेटा कमलेश डामोर (18) और परिवार के अन्य लोग खेतों में काम कर रहे थे। इसके बाद कमलेश डामोर कहीं निकल गया था, जो वापस घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की तो गांव के जंगल में एक पेड़ से उसका शव लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। वहीं, मंगलवार सुबह पुलिस ने जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गौरव सोनी और नीलमपरी ने किया प्री नेशनल 10 मीटर पिस्टल शूटिंग सीनियर वर्ग में क्वालीफाई, ऐसा करने वाला इंडिया का पहला कपल

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट उदयपुर। हाल ही में जगतपुरा जयपुर में आयोजित हुए 22वीं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में उदयपुर के गौरव सोनी और नीलम परी सोनी ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग मैं सीनियर कैटेगरी में प्री नेशनल कंपटीशन के लिए क्वालीफाई किया है जो गोवा में होने वाला है। गौरव सोनी एव नीलम परी सोनी ने पहली बार में स्टेट कंपटीशन के लिए क्वालीफाई किया है और इंडिया का पहला कपल बना है जिसने पहली बार में पति-पत्नी ने एक साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में प्री नेशनल के लिए क्वालीफाई किया। गौरव और नीलम सोनी शूटिंग का अभ्यास शिकार बड़ी में स्थित उदयपुर शूटिंग क्लब पर प्रशिक्षण लेते हैं।

लम्बे समय से अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त –शिक्षा मंत्री

24 न्यूज अपडेट

जयपुर, 23 जुलाई। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय से अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता रखते हुए दिव्यांग एवं गंभीर बीमार कार्मिकों को उनके इच्छित स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था।

शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर तथा 90 प्रतिशत आर्थोपेडिक दिव्यांग कार्मिकों को उनके वांछित स्थान पर नियुक्ति देने का संवेदनशील निर्णय लिया गया है। वांछित स्थान रिक्त नहीं होने पर उन्हें नजदीकी स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी।

इससे पहले विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधान सभा में बताया कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।

स्थानान्तरण के संबंध में सभी सम्बन्धित पक्षों जैसे आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार एवं सुझाव आमंत्रित कर विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

राजमेस के 80 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हड़ताल पर:ओपीडी में मरीजों की बड़ी लाइन

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर. डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राजमेस के 80 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। 30 डॉक्टर जयपुर धरने में शामिल होने पहुंचे। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। ओपीडी में ड्यूटी डॉक्टरों के सामने मरीजों की लाइनें बढ़ गई। मरीज को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। रूटीन के ऑपरेशन भी टाल दिए गए है। केवल इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं।

डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राजमेस से जुड़े डॉक्टर राज्य सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है। राजमेस के 80 डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से दूसरे दिन अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमराने लगी। स्पेशलिटी डॉक्टर अस्पताल के पीछे की तरफ धर्मशाला के सामने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। जबकि 30 डॉक्टर जयपुर प्रदर्शन में शामिल होने गए है। डॉक्टरों ने डाइंग कैडर का पुतला बनाकर उसका विरोध जताया। डॉक्टरों ने सरकार के आदेशों का जमकर विरोध जताया। राजमेस के डॉक्टरों के हड़ताल पर उतरने के बाद अस्पताल से जुड़े 36 डॉक्टरों को ड्यूटी पर तैनात किया है। ओपीडी में मरीजों की लाइने लग गई। ऐसे में मरीज को इलाज किए इंतजार करना पड़ा।

मौदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले बजट से सरकारी कर्मचारियों में निराशा : चौहान

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट उदयपुर। शेर सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगो जिसमें आठवां वेतन आयोग हेतु कमेटी बनाने, पुरानी पेंशन बहाल करने, बोनस की पात्रता सीलिंग बढ़ाने, आयकर में छूट की सीमा 10 लाख करने जैसी मांगो को पूरी तरह से नजर अन्दाज किया गया है। इससे कर्मचारियों में निराशा है।

बजट में पड़ोसी देशों को भारत देगा 4773 करोड़, चीन समर्थक मालदीव को झटका, पैकेज में 370 करोड़ काटे, श्रीलंका की निकल पड़ी, 4 गुना ज्यादा मदद

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, नेशनल ब्यूरो। हर बार भारत सरकार की ओर से बजट में दुनियाभर के देशों को आर्थिक मदद दी जाती है। खास तौर पर पडोसी देशों की तो बल्ले-बल्ले हो जाती हैं। ये पैसा उनको देना इसलिए जरूरी होता है ताकि वे हमारे मित्र बने रहें व विश्व मंच पर रात-बिरात में हमारे काम आ सकें। हमारे पक्ष में हमारी बातों को बुलंद कर सकें। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने पडोसी देशों सहित पूरी दुनिया के देशों को 4773 करोड रूपए का प्रस्ताव दिया है। इसमें से जोर का झटका चीन के समर्थक मालदीव को दिया है। पिछली बार के मुकाबले मालदीव को हमसे 370 करोड कम मिले हैं। श्रीलंका की निकल पड़ी है उसको इस बार हम चार गुना अधिक रकम दे रहे हैं। पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29 हजार 121 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें 6,967 हजार करोड़ की कटौती की गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में 'नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी' और 'सागर मिशन' के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है। इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। इसके अलावा कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और यूरोएशियाई देशों के लिए भी एड का प्रावधान है। सबसे ज्यादा राशि भूटान को दी गई है। भूटान के लिए 2 हजार 68 करोड़ का पैकेज रखा गया है। हालांकि, यह पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम है। श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी है। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया है। अफगानिस्तान, मालदीव और म्यांमार को मिलने वाला पैकेज कम कर दिया गया है। मालदीव को पिछले साल 770 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, जबकि इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसी के साथ भारत सरकार दूसरे देशों की मदद के लिए कुल 4 हजार 773 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा 7 अक्टूबर से इजराइल और गाजा में जारी जंग के बावजूद बजट में गाजा या फिलिस्तीन के लिए अलग से आर्थिक मदद का जिक्र नहीं किया गया है।

बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे 400 करोड़ कर दिया गया है। दरअसल, पिछले साल नवंबर में मालदीव में 'इंडिया आउट' कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार आने के बाद से दोनों देशों में तनाव है। मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की घोषणा की थी। इस साल मई में सभी 88 सैनिक भारत लौट आए। इसके अलावा 4 जनवरी को च्ड मोदी के लक्षदीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत सर्विस के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता। इस विवाद के बाद भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट आई। दोनों देशों में तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया था।

टेलीकॉम कंपनियां पूरे साल बढ़ाएंगे टैरिफ, मिनिमम 300 रूपए प्रति यूजर चपत लगाने का लक्ष्य, इस मुद्दे पर लोकसभा विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं?? क्या इसलिए कि कंपनियां देती हैं मोटा चंदा????

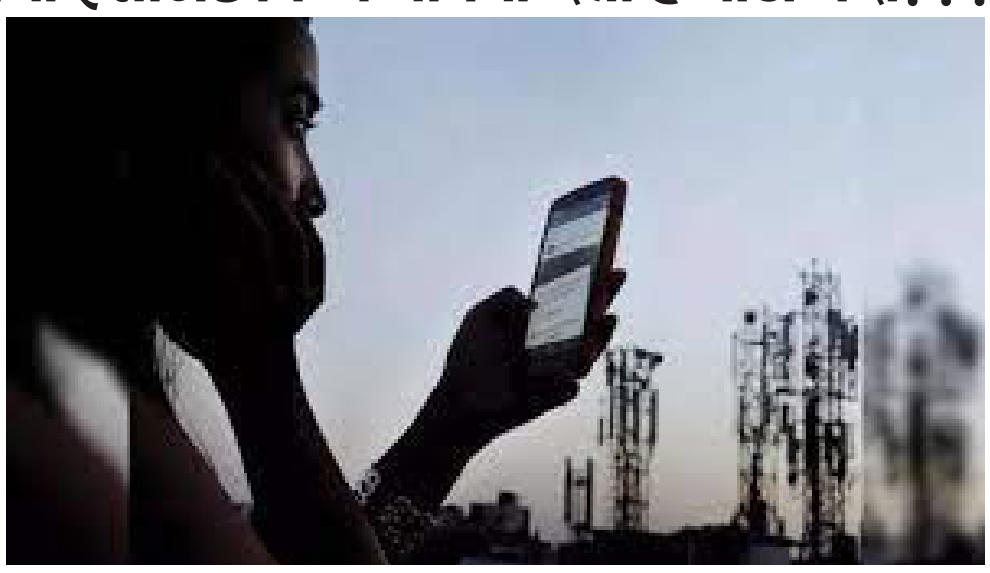

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. नई दिल्ली। फिर से तैयार हो जाइये, अब हर महीने टेलिकॉम कंपनियां जोर के झटके धीरे धीरे से देने वाली हैं। 3 जुलाई 2024 से जियो और एयरटेल सहित अन्य के रिचार्ज 25 परसेंट का जंप ले चुके है। अब इनका लक्ष्य प्रति यूजर औसत आय 300 रूपए करना है। योन कि अब धीरे धीरे रेटें बढेंगी और हर यूजर को कम से कम 300 रूपए की चपत लगाने की तैयारी है। इस मसले पर कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा है बातें बत सोशल मीडिया पर हो रही है। ना तो लोकसभा में ना ही विधानसभा में किसी ने कोई सवाल पूछा है। क्या इसलिए क्योंकि सभी कंपनियां राजनेताओं को मोटे चंदे की रकम चुनावों में देती हैं और बदले में नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाने का वचन दे दिया है। मीडिया रिपोट के अनुसार भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है, 'प्रति यूजर आय 300 तक पहुंचने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा।'आपको बता दें कि डेटा खपत 10 साल में 4 गुना बढी हैं व देश में इंटरनेट की पहुंच 52 प्रतिशत जनता तक हो गई है। गई। 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच टेलीकॉम इंडस्ट्री की आय 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। अब डेटा के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह रोटी कपडा और मकान के बाद चौथे पायदान पर आकर खडा हो गया है व इसका लाभ कंपनियां उठा रही हैं। 2023-24 में टेलीकॉम इंडस्ट्री की कुल आय 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बीते 10 साल में टेलीकॉम कंपनियां 22 से घटकर 5 रह गई। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अगले 7 सालों के दौरान भारत में टेलीकॉम में टेरिफ 36.44 परसेंट बढ जाएगा।

बजट के बाद शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1200 अंका टूटा, निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.नेशनल डेस्क। बजट के बाद शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1200 अंका टूटा, निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़ डूब गए है। बांबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 1200 अंकों की गिरावट के साथ 79224.32 अंकों पर आ गया है। सेंसेक्स 80,724.30 अंकों पर ओपन हुआ था.। निफ्टी करीब एक फीसदी की गिरावट के साथ देखा जा रहा हैं निफ्टी 232.65 अंकों की गिरावट के साथ 24,276.60 अंकों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने है. वहीं दूसरी ओर एसबीआई करीब दो फीसदी और एलएंडटी के शेयर में 4 फीसदी से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। रिलारयंस के शेयर के दाम 2927.10 रुपए पर पहुंच गए हैं तोएलएंडटी के शेयर में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट है। ओएनजीसी और श्रीराम फाइनेंस के शेयर में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, हिंडाल्को और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2.50 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों को कुछ ही घंटों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बताया गया है कि कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ाने से मार्केट में एक निगेटिव सेंटिमेंट दिखा, जिससे बाजार में गिरावट आई। हालांकि, लंबे समय में ये सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका छोटे निवेशकों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं, बड़े निवेशकों के लिए भी 2.5 परसेंट टैक्स बढ़ने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

केंद्रीय बजट में राजस्थान को मिला नया इंडस्ट्रियल एरिया:जोधपुर-पाली, मारवाड़ प्रोजेक्ट को मंजूरी; टैक्स की हिस्सेदारी 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा हुई

24 न्यूज अपडेट

जयपुर.केंद्रीय बजट में राजस्थान को नया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देने की घोषणा की गई है। इसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। राजस्थान को केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को फायदा होगा।

कृषि क्षेत्र में राजस्थान दाल का बड़ा उत्पादक है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा की है। इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। इसका बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा।

5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी फायदा मिलेगा।

कुछ सवालों से समझिए, बजट में राजस्थान को क्या-क्या मिला?

1. राजस्थान से जुड़ी बड़ी घोषणा क्या है, क्या फायदा मिलेगा?

जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये 1578 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा। इस पर 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिख रही थी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने भी JPIMA को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे थे। राज्य सरकार ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 275 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पास विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जोधपुर और पाली शहर से बराबर दूरी 30 किलोमीटर पर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है।

2. राजस्थान को केंद्र से ज्यादा पैसा मिलेगा?

केंद्र से राजस्थान को इस बार टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीतारमण की ओर से पेश बजट में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में यह जानकारी दी गई है।

पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 66,556 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस साल इस राशि में करीब 7 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत है।

3. सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का क्या फायदा होगा?

जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी की मंडी भी कहा जाता है। सूरत के बाद जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा बाजार है। बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6 प्रतिशत की गई है। इसका सीधा फायदा जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को होगा।

जयपुर में हर साल करीब 5 हजार करोड़ का सोना-चांदी इंपोर्ट होता है। कस्टम ड्यूटी घटने से इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी। इससे आमजन को भी सीधा फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कदम से ज्वेलरी इंडस्ट्री में बूम आएगा।

4. दलहन और तिलहन की पैदावार करने वाले किसानों को क्या फायदा?

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया- राजस्थान का देश में दलहन में दूसरा और तिलहन में तीसरा-चौथा स्थान है। हर साल 80 लाख दलहन का उत्पादन करता है। वहीं 82 लाख टन तिलहन का उत्पादन करता है। 60 लाख टन सरसों की पैदावार हर साल होती है। राजस्थान सरसों उत्पादन में देश में नंबर-एक पर है। ऐसे में इस घोषणा का फायदा प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा होगा। किसान की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी।

सीएम बोले- लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट

सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री कार्यालय में सुना। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की राह पर ले जाने वाला लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट है।

नेता प्रतिपक्ष बोले- केंद्रीय बजट में राजस्थान खाली हाथ

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय बजट को सरकार को बचाने और जनता को बहलाने वाला बताया है। जूली ने कहा- बजट का एकमात्र विजन सरकार को बचाना है। बजट में 41,000 करोड़ सरकार के सहयोगी प्रदेशों को दिए गए हैं, जो कि अन्य राज्यों के हितों पर कुठाराघात है। केंद्र ने अपनी सरकार को बचाने वाले बिहार को 26,000 और आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए दिए हैं। डबल इंजन सरकार की दुहाई देने वाले राजस्थान को बजट में सिर्फ आश्वासन मिला है।

युवक ने फतहसागर झील में कूदकर किया सुसाइड

प्रत्यक्षदर्शियों ने छलांग लगाते देखा, रेस्क्यू ऑपरेशन में दो के मिले शव

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर. उदयपुर की फतहसागर झील में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। एक युवक को लोगों ने सोमवार को झील में छलांग लगाते देखा था। पानी में उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था लेकिन पता नहीं चला। आज सुबह वापस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें युवक के साथ ही एक अन्य व्यक्ति का भी शव मिला। अंबामाता थाना पुलिस ने शवों को एमबी हॉस्पिटल मॉच्यूरी में रखवाया। पोस्टमार्टम बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति ठीक नही थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। वहीं दूसरे व्यक्ति के डूबने के पीछे का कारण सामने नहीं आया है।

युवक की बाइक सड़क किनारे मिली

पुलिस के अनुसार एक दिन पहले विवेक खारोल (23) नाम का युवक झील में डूबा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे रानी रोड वाले छोर से झील में छलांग लगाते हुए देखा था। युवक की बाइक रोड किनारे खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को बचाने का प्रयास किया लेकिन पानी में गहराई में जाने से युवक की मौत हो गई।

जेब में मिला कागज

दूसरे मृतक की पहचान नंदकिशोर सुहालका(45) निवासी गायरियावास के रूप में हुई है। वह सुबह अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। उस दौरान फतहसागर झील में डूब गए। उनकी जेब से एक कागज मिला है जिसमें नंदकिशोर गायरियावास सुहालका देशी शराब लिखा है। रेस्क्यू टीम में गोताखोर पुरुषोत्तम कुमावत, कपिल सालवी, विपुल चौधरी, हीरालाल प्रजापत और हितेश सोलंकी आदि शामिल थे।

बिजली के पोल पर आधा घंटे तक लटका रहा लाइनमैन

करंट के बाद लगी आग, एक पैर कटकर हुआ अलग; क्रेन से उतारी डेडबॉडी

24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा. बिजली के पोल पर लाइन को ठीक कर रहे ठेकाकर्मी लाइनमैन की करंट से मौत हो गई। युवक का एक पैर कटकर अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे तक युवक का शव तारों पर लटका रहा। मामला भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके का मंगलवार सुबह 11 बजे का है। ASI चिराग अली कायमखानी ने बताया- मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला सौरभ पटेल (22) भीलवाड़ा में बिजली विभाग में ठेकेदार के पास लाइनमैन था। मंगलवार को सौरभ बापूनगर इलाके की हेमू कॉलोनी पार्क के पास ट्रैक्टर क्रेन पर चढ़कर बिजली लाइन पर काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली सप्लाई चालू होने से करंट दौड़ गया। सौरभ पोल और लाइन से चिपक गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे का पता चलते ही कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई बंद की। प्रतापनगर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पहुंचे। दोपहर 12 बजे लाइनमैन का शव क्रेन की मदद नीचे उतरा गया। पोस्टमॉर्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिजवाया। जानकारी के अनुसार सौरभ 4 दिन पहले ही भीलवाड़ा आया था। वह परिचित के पास ठहरा था। उसका परिवार सागर में ही रहता है। ठेकेदार ने कर्मचारी को सौरभ के गांव भेजा है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। मामले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (एसई) वीके संचेती को दो बार कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।

वनरक्षक भर्ती के आरोपियों का पता बताने पर मिलेगा कैश

हरीश पर 25 हजार और छगन पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित

24 न्यूज अपडेट

बांसवाड़ा. जिले में नवंबर 2022 में हुई वनरक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में दोनों आरोपियों पर एसओजी ने इनाम घोषित किया है। पेपर लीक मामले में जिले में सरगना के रूप में बांसवाड़ा निवासी छगन और बाड़मेर निवासी हरीश की पहचान हुई थी। पुलिस ओर एसओजी दोनों को ही आरोपियों की तलाश है।

एएसपी एसओजी लाखन सिंह ने बताया वनरक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले के दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। अतिरिक्त महानिदेशक ने दोनों आरोपियों पर हरीश 25 हजार और छगन 10 हजार रुपए इनाम घोषित किया है।

पता बताने वाले को कैश इनाम

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी के परिस देशमुख ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि बाड़मेर के अरटवाव गुड़ामलानी निवासी हरीश उर्फ हीराराम पुत्र रतनाराम सारण पर 25 हजार का इनाम घोषित किया है। साथ ही बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के भीलकुआं निवासी छगन पुत्र पूनमचंद पारगी के ऊपर 10 हजार कर इनाम घोषित किया।

आदेश में यह भी कहा गया है कि दोनों आरोपियों को आसपास के जिलों और संभावित राज्यों में तलाश की गई पर कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में इन दोनों आरोपियों को कोई गिरफ्तार करेगा या करवाएगा या फिर कोई सही जानकारी देगा तो नियमानुसार नगद इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि हरीश ने छगन के जरिए की बांसवाड़ा के अभ्यर्थियों को वनरक्षक भर्ती परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले पेपर हल करवाया था। बांसवाड़ा शहर के 2 घरों में दोनों पारियों से पहले पेपर हल कराए थे। इस मामले में अब तक कुल 12 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 6 वनरक्षक थे।

24 न्यूज अपडेट

देश-दुनिया राज्यों एवं स्थानीय खबरें को देखने के लिए
हिन्दी समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल

ताजा खबरें देखने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें

YouTube

24 NEWS UPDATE

हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें

लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।